राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

भारत को झटका धवन विश्वकप से बाहर

>> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 10

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, गुरुवार, 20 जून 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर मोदी सरकार बनाएगी पैनल

सर्वदलीय बैठक ▶ अधिकतर दलों ने चर्चा के दौरान विचार का किया समर्थन : राजनाथ

बैठक में बीजद, राकांपा, नेकां, टीआरएस समेत 21 दल हुए शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पैनल का गठन करेंगे, जो तय समय के भीतर काम पूरा करेगा। इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी। बैठक का कांग्रेस समेत तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, द्रमुक जैसे कई दलों ने बहिष्कार किया, जबकि शिवसेना को छोड़कर राजग के सहयोगी दलों के साथ-साथ विपक्ष से राकांपा, नेकां, टीआरएस, बीजद और वाम दल बैठक में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि पार्टी स्थापना दिवस होने की वजह से शिवसेना बैठक में शामिल नहीं हुई।

प्रधानमंत्री ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समेत पांच मुद्दों पर विचार करने के लिए बुधवार को बैठक बुलाई थी। इसके लिए 40 दलों को न्योता भेजा गया था, लेकिन बैठक में 21 दलों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधि ही शामिल हुए। तीन ने लिखित में अपनी प्रतिक्रिया भेजी। इन पांच मुद्दों में एक साथ चुनाव के साथ-साथ, संसद की उत्पादकता बढ़ाने, स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर न्यू इंडिया के निर्माण, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम और पिछड़े हुए आकांक्षी जिलों के विकास पर चर्चा शामिल थी।

बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से कहा, अधिकतर दलों ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार का समर्थन किया है। वाम दलों के इस लागू करने को लेकर विचार अलग थे। वहीं, भाजपा समेत कई दलों का मानना था कि एक साथ चुनाव समय की मांग है और देश को एक बार फिर से इस दिशा में बढ़ना चाहिए।

सिंह के मुताबिक, बैठक में मोदी ने साफ किया कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' राष्ट्रीय मुद्दा है। इसे किसी एक दल या सरकार का एजेंडा नहीं माना जाना चाहिए। इसमें सभी दलों के विचार को शामिल किया जाएगा। बैठक में मौजूद सभी दलों के विचार को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कमेटी गठित करने की बात कही और सबने सहमति जताई। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव एस सुधाकर रेड्डी, बिहार के सीएम व जदयू नेता नीतीश कुमार, शिअद नेता सुखबीर सिंह बादल, ओडिशा के सीएम और बीजद प्रमुख नवीन पटनायक और नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता कोनार्ड संगमा भी बैठक में शामिल हुए। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला और एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी भी बैठक में मौजूद रहे। सीताराम येचुरी और ओवैसी ने इस विचार का विरोध किया। येचुरी ने कहा, यह संघीय भावना के विपरीत है। भाजपा बैकडोर से संसदीय लोकतंत्र की जगह राष्ट्रपति प्रणाली जैसी व्यवस्था लाना चाहती है।

कांग्रेस ने अंतिम समय में बैठक में न जाने का ऐलान किया। पार्टी प्रवक्ता गौरव गोगोई ने कहा, यह असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ही सरकार को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई थी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, बसपा प्रमुख मायावती, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में नहीं शामिल हुए है। ममता बनर्जी ने इस पर श्वेत पत्र लाने की मांग की, जबकि मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अगर बैठक ईवीएम को लेकर होती तो वह जरूर शामिल होतीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बैठक में शामिल नहीं हुए।

ज्ञात हो, एक साथ चुनाव भाजपा के एजेंडे में टॉप पर है और इसे चुनाव सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 2014 से ही इस बाबत अपील करते रहे हैं।

विभिन्न दलों के अध्यक्षों के साथ शानदार बैठक हुई। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की गई। मैं विभिन्न नेताओं को उनके अहम सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं।-नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली में बुधवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक में जदयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राकांपा प्रमुख शरद पवार, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक व आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी शामिल हुए। प्रेट्र

कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा पार्टी लाइन से हटकर केंद्र के साथ

नई दिल्ली, एएनआइ : कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विचार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, सरकार के प्रस्ताव पर खुले मन से विचार किया जाना चाहिए। उन्हें अभी तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं कि एक साथ चुनाव कराने से केंद्र में सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलेगा। हाल ही में लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। ओडिशा और आंध्र में वे दल जीते जिनका भाजपा के साथ गठबंधन नहीं था।

विधि आयोग इसके लिए सख्त कानूनी ढांचे के पक्ष में

नई दिल्ली, प्रेट्र : विधि आयोग ने गत वर्ष मसौदा सिफारिशों में संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की बात की थी ताकि एक साथ चुनाव सुनिश्चित हो सकें। आयोग ने कहा था कि लोस और विस के चुनाव दो चरणों में कराए जा सकते है बशर्ते संविधान के दो प्रावधानों में संशोधन हों और बहुमत से राज्यों द्वारा उनका अनुमोदन किया जाए।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अभी संभव नहीं : चुनाव आयोग

नई दिल्ली, आइएएनएस : चुनाव आयोग का कहना है कि फिलहाल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करना संभव नहीं है। आयोग के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि अगर ऐसा संभव होता तो आयोग इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ ही करा लेता। इसके लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की जरूरत होगी, जबकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या सीमित है। सूत्रों ने यह भी कहा कि देश में इस समय 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनके लिए बड़ी संख्या में मतदान अधिकारी, ईवीएम और अन्य संसाधनों की जरूरत होगी, जिसे जुटा पाना फिलहाल संभव नहीं है।

लोकतंत्र के प्रहरी

आपातकाल के 44 साल

ब्रिटिश सरकार से ज्यादा जुल्म आजाद भारत में सहे

आपातकाल के दौर में जेल की यातना यादकर आज भी उरई के राजाराम व्यास सिहर उठते हैं। बताते हैं कि पानी मांगने पर मूत्र पीने को दिया जाता था। पुलिस पेड़ से लटकाकर पीटती थी। मानसिक यातना भी कम नहीं थी। परिजनों के पत्र जेल के अधिकारी पढ़ने के बाद देते थे। ● पेज 13

हमारी सरकार

डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक', मानव संसाधन विकास मंत्री

आचार्य से शुरू सफर को मिला अहम मुकाम

● पेज 5

विश्वास News

वायरल नंबर योगी आदित्यनाथ का नहीं, जीआरपी का है ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज 7

सरोकार

ये है हुनरमंद सखियों का करोड़पति मंडल

गोड्डा : झारखंड के गोड्डा जिले का फूलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल कई

मायनों में खास है। महिलाओं की लगन और मेहनत ने सखी मंडल को करोड़पति बना दिया है। कभी गरीबी से जूझने वाली गांव की महिलाएं आज हुनरमंद बन गुरबत को हरा चुकी हैं। मंडल का कारोबार पांच करोड़ के पार पहुंच गया है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि इसको एसोचैम ने सम्मानित किया है। मंडल से जुड़ी हर सखी सात से आठ हजार रुपये महीने कमा रही है। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

खशोगी हत्याकांड में सऊदी युवराज के खिलाफ पुख्ता सुबूत

जिनेवा : पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में सऊदी अरब के युवराज मुहम्मद बिन सलमान के खिलाफ पुख्ता सुबूत मिले हैं। यह बात संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्य करने वाली मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कही है। इस जांच निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने मुहम्मद की विदेशी संपत्तियों की जब्ती की मांग की है। खशोगी की अक्टूबर 2018 में तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास में उस समय हत्या हुई थी जब वह अपने वीजा से संबंधित दस्तावेज पेश करने गए थे।

क्रिकेट महाकुंभ

ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश

दोपहर 3:00 बजे से

स्थान : नॉटिंघम

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

पाकिस्तान सीमा पर रणनीति बदलेगी सेना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अक्टूबर से होगी विशेष वार ग्रुप की तैनाती, युद्ध के जरूरी हथियारों से लैस रहेंगे ये फौजी दस्ता
- हमले और बचाव के लिए होंगे अलग दल, अगले चरण में चीन सीमा पर भी होगी तैनाती

पाकिस्तान की नापाक हरकतों और चीन से आए दिन के खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना रणनीतिक रूप से खुद को बेहतर करने का काम कर रही है। सीमा के पास लगातार बढ़ रहे खतरों को भांपते हुए भारतीय सेना ने खास रणनीति के तहत इसी साल अक्टूबर से पाकिस्तान से लगी सीमा पर 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' (आइबीजी) तैनात करने की योजना बनाई है। बाद में इसे चीन से लगी सीमा पर भी तैनात किया जाएगा।

आइजीबी के तहत आर्टिलरी गन, टैंक, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक जैसे सेना के अलग-अलग घटकों को एक साथ लाया जाएगा। यह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार समूह होगा। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के प्रयासों के बीच यह रणनीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस रणनीति में रक्षात्मक भूमिका को मजबूती देते हुए पहले के मुकाबले ज्यादा थल सैनिकों को सीमा पर तैनात किया जाएगा। इनका काम मुख्य स्ट्राइक ग्रुप का साथ देना और अपने क्षेत्र का बचाव करना होगा।

युद्ध की स्थिति में दुश्मनों की सीमा में सेना की टुकड़ियों को तेजी से भेजने और त्वरित कार्रवाई के मकसद से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाया गया है। यह इतनी तेजी से कार्रवाई करेगा कि दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। आइबीजी छोटा होगा और युद्ध के लिए आवश्यक सभी हथियार और सैनिकों से लैस होगा। आइजीबी की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के हाथ में हो सकती है। एक ग्रुप में करीब 5,000 सैनिक होने की उम्मीद है। साल के आखिर तक कम से कम ऐसे तीन ग्रुप तैयार हो जाएंगे।

इस कॉन्सेप्ट को साकार करने के लिए सेना के पूर्वी कमांड के अंतर्गत इस खास युद्ध रणनीति का अभ्यास किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, यह युद्धक फॉर्मेशन बेहद घातक होगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के अभ्यास और उसके फीडबैक को लेकर पिछले हफ्ते विस्तार से चर्चा हुई। सेना मुख्यालय में हुई बैठक में सात आर्मी कमांडरों ने भाग लिया। बैठक में कमांडर-इन-चीफ को ये निर्देश दिए गए कि वो अपने-अपने इलाकों में आइबीजी का निर्माण कराएं। पहले तीन ग्रुप पूर्वी कमांड की फॉर्मेशन की तर्ज पर बनाए जाएंगे। यह ग्रुप सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की उस खास रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो सेना को ज्यादा प्रभावशाली और खतरनाक बनाना चाहते हैं।

ब्रिगेड व्यवस्था की जगह लेगा आइबीजी : असल में सेना इस कॉन्सेप्ट को ब्रिगेड व्यवस्था की जगह लाना चाहती है। आइबीजी अपने आप में युद्ध की स्थिति से निपटने में सक्षम टीम होगी। वहीं ब्रिगेड व्यवस्था को युद्ध की स्थिति में साजो-सामान के लिए इंतजार करना पड़ता है। ब्रिगेड में कम से कम तीन से चार यूनिट होती हैं। प्रत्येक यूनिट में 800 सैनिक होते हैं।

अब किसी भी नापाक हरकत पर सेना साधेगी सटीक निशाना पेज>>6

ओम बिरला बने सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कोटा से सांसद बिरला को अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए प्रधानमंत्री मोदी
- कांग्रेस, तृणमूल समेत सभी विपक्षी दलों ने बिरला पर जताया भरोसा

राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला बुधवार को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और चुने जाने के बाद अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए। इस अवसर पर जहां पीएम ने बिरला की विनम्रता व समाजसेवा के भाव की तारीफ की, वहीं विपक्षी दलों ने सदन को निष्पक्षता से चलाये जाने की उम्मीद जताई।

ओम बिरला की विनम्रता की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा, उनका जीवन अनुशासन और समाजसेवा का रहा है। उम्मीद है कि वे सदन को अपने अनुशासन से अनुप्रेरित करेंगे। पीएम ने कहा,बिरला की कार्यशैली में सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि समाजसेवा है। समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए वह सदैव प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह बिरला गुजरात में 2011 के भूकंप के दौरान राहत कार्य में जुटे थे। केदारनाथ त्रासदी के समय भी लोगों की मदद के लिए पहुंच गए थे। कोटा की जनता की सेवा के लिए भी आधी रात को कंबल लेकर निकलते थे। कोटा में कोई भूखा न सोए इसके लिए प्रसादम नाम की योजना भी चला रहे हैं।

सुबह लोकसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही पीएम ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए बिरला का नाम प्रस्तावित किया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने इसका समर्थन किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सपा, बसपा समेत समूचे विपक्ष ने भी साथ दिया और बिरला ध्वनिमत से अध्यक्ष चुने गए। बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए सांसदों को आश्वासन दिया कि वह किसी भी दल के हों, वह उनके हितों का ध्यान रखेंगे। सदन की कार्यवाही में सभी नियमों व नियमावलियों का पूरा पालन करेंगे। उन्होंने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के सदस्यों से सहयोग मांगा। इसके बाद बिरला ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उसके बाद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आवास पर जाकर उनसे मिले।

लोकसभा का अध्यक्ष बनते ही सामने आई मांगों की लंबी फेहरिस्त पेज>>3

नई दिल्ली में बुधवार को भाजपा सांसद ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। पीएम मोदी उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गए। इस दौरान आभार जताते ओम बिरला (टीवी ग्रैब)। प्रेट्र

मानसून की धीमी चाल से सब परेशान, सूखे की आशंका

मुंबई : भारत में करीब एक हफ्ते देरी से केरल पहुंचे (आठ जून) मानसून की गति औसत से भी धीमी है। जून में अब

तक बारिश औसत से 44 फीसद कम हुई है। इसके चलते खेती चौपट होने के साथ ही देश के कई हिस्से में भीषण सूखे की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। बारिश में कमी से उपभोक्ताओं की मांग, अर्थव्यवस्था की चाल और बाजार के हाल पर बहुत गंभीर और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने इस साल औसत बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं मौसम का हाल बताने वाली देश की इकलौती निजी एजेंसी स्काईमेट ने औसत से कम बारिश का अनुमान जताया है। (पेज-5)

रेलवे बढ़ाएगी रफ्तार : दिल्ली से 12 घंटे में कोलकाता और 10 घंटे में मुंबई पहुंचेगी ट्रेन

- रेलवे ने तैयार किया 100 दिन की कार्ययोजना का मसौदा
- दो ट्रेनों और कुछ रेल मार्गों को निजी हाथों में सौंपने की भी तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों को 100 दिन का एजेंडा तय करने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में रेलवे ने योजना तैयार की है, जिसके तहत दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई के बीच रेल यात्रा के समय में पांच घंटे की कमी लाने का लक्ष्य है। रेलवे इसके लिए अगले चार साल में इन दोनों मार्गों पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 14,000 करोड़ का निवेश करेगी। रेलवे ने 10 और प्रस्ताव भी तैयार किए हैं। 31 अगस्त तक इन्हें लागू करने को तत्काल कार्य शुरू करने की बात भी कही है। इन दोनों व्यस्त रेल मार्ग पर देश की कुल यात्री ट्रेनों में से 30 फीसद और 20 फीसद मालगाड़ियों का आना-जाना रहता है।

मौजूदा समय में दिल्ली से हावड़ा की दूरी तय करने में सबसे तेज रफ्तार ट्रेन को 17 घंटे, जबकि दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 15.5 घंटे लगते हैं। 100 दिन की योजना में इन दोनों ही मार्ग पर यात्रा समय को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के पास भेजा जाना है।

प्रस्ताव के मसौदे के मुताबिक, अभी इन दोनों ही रूट पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रतिघंटे है, जिसे बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रतिघंटे किया जाना है। इस प्रोजेक्ट पर नई दिल्ली-हावड़ा रूट (1,525 किलोमीटर) पर 6, 684 करोड़ और दिल्ली-मुंबई रूट (1,483) पर 6,806 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मंजूरी मिलने के बाद चार साल का समय लगेगा। अन्य 10 प्रस्तावों में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई 'गिव इट अप' योजना शामिल है, जिसके तहत लोगों को रेल टिकट पर सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अगले 100 दिन की योजना में कम भीड़ वाले रेल मार्गों और दो ट्रेनों के संचालन को निजी हाथों में सौंपा जाना भी शामिल है। इसके अलावा सभी 6,485 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराना, 2023 तक सभी 2,568 लेबल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए मंजूरी हासिल करना और अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली इत्यादि लागू करना शामिल है।

फिर शुरू हुई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने की कोशिश पेज>>3

विश्वास की कमी

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लोगों की भावना व अपेक्षा को समझ नहीं रही है, कांग्रेस के व्यवहार से आशंका होती है वह न सिर्फ संख्या में बल्कि सोच और मनोबल में भी छोटी होने लगी है

...कांग्रेस की एक और गलती

त्वरित टिप्पणी

प्रशांत मिश्र

- एक साथ चुनाव पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार पड़ेगा भारी

कांग्रेस की सोच समझ से परे है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो आचार व्यवहार रहा, उसकी बात छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि जनता ने ही उसका जवाब दे दिया। जनादेश ने जिस तरह कांग्रेस को लगातार दूसरी बार दस फीसद सीटों से भी नीचे खड़ा कर दिया, वह यह बताने के लिए काफी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी लोगों की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। वह जनता की भावना व अपेक्षा को नहीं समझ पा रही है। अफसोस तो यह है कि बार-बार के झटके के बावजूद कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रही है। एक देश, एक चुनाव यानी एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का जिस तरह कांग्रेस ने बहिष्कार किया, वह साबित करता है कि कांग्रेस गलतियों से सीख लेने के लिए तैयार नहीं है।

अभी दो दिन पहले 17वीं लोकसभा की शुरुआत के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बयान आया था कि विपक्ष को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास कितने नंबर हैं। उन्हें अपने विचार रखने चाहिए और सरकार हर किसी के विचार को सुनकर आगे बढ़ेगी। तत्काल कांग्रेस की ओर से उत्तर आया था और उम्मीद जताई गई थी कि विधेयकों पर विपक्ष की राय सुनी जाएगी और बहुमत के

राहुल गांधी फाइल फोटो

बल पर उसे नहीं दबाया जाएगा। एक तरह से कांग्रेस ने तंज किया था। फिर बुधवार को कांग्रेस को क्या हो गया..? प्रधानमंत्री की ओर से एक बैठक बुलाई गई और कांग्रेस अपने विचार रखने तक को आने को तैयार नहीं हुई। कई छोटे विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है लेकिन कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है। आज भी पांच राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। क्या उसके लिए यह उचित नहीं था कि बैठक में आए और विरोध करना है तो विरोध ही करे। तर्कों के साथ अपनी बात रखे। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और उसके सलाहकारों की बलिहारी, उसने तो हार ही मान ली।

कांग्रेस के इस व्यवहार से आशंका जरूर होगी कि वह न सिर्फ संख्या में बल्कि सोच और मनोबल में भी छोटी होने लगी है। डरी हुई है। इस कोशिश में है कि किसी भी मुद्दे पर विरोधी दलों के साथ ही खड़ी रहे ताकि एक खेमा तो बना रहे। यह डर कांग्रेस के लिए खतरनाक है। बैठक में सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था। अगर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं आ सकते थे तो किसी भी दूसरे वरिष्ठ नेता को भेजा जा सकता था जो तर्कों के साथ यह बात रख पाते कि एक साथ चुनाव कराना देश के हित में नहीं है। दरअसल अब तक अलग-अलग मंचों से जितनी भी चर्चा हुई है, उसमें यही बात मानी गई है कि एक साथ चुनाव हुए तो देश का पैसा भी बचेगा, वक्त भी और विकास की धारा भी अवरुद्ध नहीं होगी। वह पैसा, वह वक्त जनता का है। इसका विरोध करने वाले दल व्यावहारिकता आदि की दलील देते रहे हैं। सच्चाई यह है कि इसके पीछे दलों का डर छिपा है। बैठक से बाहर रहकर कांग्रेस ने इसे जाहिर कर दिया। अब उसे यह सोचना चाहिए कि जनता को कैसे समझाएगी।

महाराष्ट्र में 4 हजार से ज्यादा महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए

राज्य ब्यूरो, मुंबई : महाराष्ट्र के बीड जिले में 4,605 महिलाओं के गर्भाशय सिर्फ इसलिए निकाल दिए गए, ताकि वह अनवरत गन्ने की कटाई का काम कर सकें। महाराष्ट्र विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने इसका रहस्योद्घाटन किया। इस घटना की जांच के लिए सरकार ने एक पैनल गठित कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, पिछले तीन साल में मराठवाड़ा के बीड जिले में 4,605 महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए। बीड जिला सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित समिति की जांच में इस बात का पता चला। रिपोर्ट के अनुसार, बीड में निजी क्षेत्र के 99 अस्पतालों में 2016-17 से 2018-19 के बीच इतनी बड़ी संख्या में 25 से 30 वर्ष आयुवर्ग की महिलाओं की अज्ञानता का लाभ उठाकर गर्भाशय निकाले गए। स्वास्थ्य मंत्री ने विधान परिषद में शिवसेना की दो महिला सदस्यों नीलम गोरे एवं मनीषा कायंदे के सवालों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने महिलाओं के गर्भाशय निकाले जाने की जांच के लिए बुधवार को एक पैनल का गठन किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव इसका नेतृत्व करेंगे। इस पैनल में तीन स्त्री रोग विशेषज्ञ और कुछ महिला विधायक भी शामिल होंगी। पैनल दो माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा।

YOUR DREAM, OUR MISSION

YOUTH DESTINATION

IAS • PCS

सामान्य अध्ययन

By Rajnish Raj Sir

निःशुल्क कार्यशाला से बैच प्रारंभ

21 June

ONLINE/ LIVE CLASS AVAILABLE

11:30 AM

ETHICS

25 June 3:30 PM

By अभय कुमार सर

9811334434, 9811334480

web : www.youthdestination.in | youtube: youthdestinationias | FB: youthdestinationias

639, DR. MUKHERJEE NAGAR, OPP. SIGNATURE APARTMENT , DELHI-110009